जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 344 प्रभात चूरू, शनिवार 15 अप्रेल, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

अलास्का से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैले द्वीप समूह, अलूशन आइलैण्ड्स पर लावा बहने से बने टेढ़े मेड़े व ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र में लाखों की संख्या में क्रैस्टेड व लीस्ट ऑक्लैट्स रहते हैं। यहाँ ऑक्लैट्स का न्यूट्रिएन्ट्स से भरपूर मल भूमि को फर्टिलाइज़ करता है, जिससे घास के घने पैंच पनपते हैं। लेकिन एक नए शोध में सामने आया है कि, ऑक्लैट्स की, स्वयं की पनपने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि, समय -समय पर लावा इस क्षेत्र को साफ कर दे। यदि लैण्डस्केप बहुत अधिक हरा-भरा हो जाता है तो ये पक्षी अपना आवास खो बैठते हैं। अलास्का मैरीटाइम नैशनल वाइल्डलाइफ रिफ्यूज की जीव वैज्ञानिक हैंदर रैनर, ने कहा कि, गत कुछ वर्षों से अलूशन द्वीपों पर ऑकलैट्स का शोर कम हो गया है। शोध के अनुसार इनकी विशाल कॉलोनियाँ छोटी हो गई हैं और 18 वीं सदी के बाद से आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियाँ लुप्त हो गई हैं। हालांकि अलूशन द्वीपों के उत्तर में बैरिंग सी रेंज में यह स्थिति दिखाई नहीं दी है। इस रहस्य को जानने के लिए रैनर ने ऑक्लैट्स की ब्रीडिंग कॉलोनियों का परीक्षण किया, जहां मादा ऑक्लैट्स लावा प्रवाह से बनीं प्राकृतिक दरारों में घुसकर अण्डे देती हैं। इस क्षेत्र में इतनी दरारें है कि, लाखों ऑक्लैट्स प्रजनन कर सकती हैं। इनके पंखों और बीट के आधार पर रैनर ने कॉलोनी की सीमा मापी। उन्होंने पाया कि, नए लावा प्रवाह वाले क्षेत्रों में, जहाँ हरियाली नहीं है, वहाँ ऑक्लैट्स की बड़ी कॉलोनियाँ हैं। लावा, जो सब कुछ नष्ट कर देता है, ऑकलैट्स कॉलोनियों की बेहतर हैल्थ का आधार है। रैनर ने कहा, अगर अलूशन ज्वालामुखी एक्टिव नहीं होते तो यहां ऑक्लैट्स की कॉलोनियां भी ज्यादा नहीं होतीं। हालांकि, ऑक्लैट्स जमीन पर घर बनाते हैं पर उनकी बीट दरारों के आस-पास जमा हो जाती हैं। समय बीतने के साथ इससे जमीन बहुत अधिक उर्वर और हरी भरी हो जाती है, फिर यह क्षेत्र ऑक्लैट्स के रहने लायक नहीं रहता। रैनर ने कहा, सिकुड़ता प्राकृतिक आवास ऑक्लैट्स के लिए आपदा का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक चक्र है। उदाहरण के लिए, यहां के किस्का आइलैण्ड पर 40 के दशक में ऑक्लैट्स की सबसे बड़ी कॉलोनी थी, धीरे-धीरे यहां घास उगने लगी और ऑक्लैट्स की संख्या कम हो गई फिर 60 के दशक में नया ज्वालामुखी फटा और यह द्वीप फिर से ऑक्लैट्स की बड़ी बस्ती बन गया।

'पायलट 17 अप्रेल को अपनी दो रैलियों में क्या कहेंगे?'

यह जिज्ञासा सर्व व्यापक है, पर जवाब सीधा है, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जैसा उन्होंने वसुंधरा राजे के ''भ्रष्टाचार'' के बारे में अनशन के दिन दिया था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। सब की नज़रें एक बार फिर सचिन पायलट पर लगी हैं तथा इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि 17 अप्रैल को झुँझुँनूँ तथा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र दो जन-सम्पर्क कार्यक्रम के दौरान, वे क्या कहेंगे।

ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी उस मुहिम को आगे बढ़ायेंगे, जो उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ शुरु की थी।

सूत्रों का कहना है कि अब उनका रूकना संभावित नहीं लग रहा क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टी तथा मुख्यमंत्री को पिछले चार वर्षों में उठाने चाहिये थे तथा उनसे निबटना चाहिये था।

इस बीच, ए.आई.सी.सी. महासचिव रंधावा को, उनके द्वारा अशोक गहलोत का अति उत्साहपूर्ण समर्थन किये जाने के बाद, कांग्रेस नेतृत्व ने साफतौर पर अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया है।

पार्टी के सूत्रों का कहना है कि रंधावा और जयराम रमेश दोनों के लिये ही एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट को उस समय दबाने एवं नीचा दिखाने की कोशिश की, जब वे एक भाजपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे।

एक पार्टी नेता ने कहा कि रंधावा और जयराम रमेश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सचिन पायलट का यह कदम पार्टी-विरोधी कैसे मान लिया गया। सूत्रों का कहना है कि यह तथ्य, कि राजस्थान के प्रकरण में अब कमलनाथ की एंट्री हो गई है, इस बारे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- फिलहाल महासचिव रंधावा, ए.आई.सी.सी. के लिये अवांछनीय व्यक्ति हो गये हैं, जब से उन्होंने मु.मंत्री गहलोत के लिये ''बैटिंग'' करना शुरू कर दिया है।
- रंधावा व जयराम को अपनी सफाई देना मुश्किल हो रहा है कि, उन्होंने कैसे और क्यों पायलट को नीचा दिखाने का प्रयास किया, जब वे एक भाजपा नेता के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे।
- इन दोनों को यह समझाना मुश्किल हो रहा है कि, पायलट का वसुंधरा राजे पर आरोप लगाना ''एन्टी पार्टी'' कृत्य कैसे हो गया।
- बहरहाल कमलनाथ को राजस्थान के तथाकथित राजनीतिक संघर्ष को सुलझाने की जिम्मेवारी सौंपना भी उल्लेखनीय है, क्योंकि, कमलनाथ सोनिया गांधी व राहुल गांधी के अतिविश्वासी व्यक्ति हैं तथा वे संघर्ष को उसी तरह सुलझायेंगे, जैसा सोनिया व राहुल का मन है।
- और, दोनों का मन गहलोत से खिन्न है तथा गहलोत की, गांधी परिवार से मिलने की चेष्टा को एक ही जवाब मिल रहा हैः ''नो एन्ट्री''।
- पर, गहलोत-पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहते, वे तो पायलट को बोरिया बिस्तर सहित दिल्ली भेजना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने 12, तुगलक रोड से अपना सामान शिफ्ट करना शुरू किया

राहुल ने दो ट्रक पर्सनल सामान, 10, जनपथ, सोनिया गांधी के निवास पर भेजा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। राहुल गांधी ने अपने आवास 12 तुगलक़ लेन को खाली करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। उनके निजी सामानों से भरे दो ट्रक पहले ही उनकी माँ सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर भेज दिए गए हैं।

राहुल के पास अपना आवास खाली करने के लिए 22 अप्रेल तक का समय है और उम्मीद है कि वह अपने आवास की चाबियाँ उक्त तिथि से पूर्व ही सुपुर्द कर देंगे। राहुल गांधी वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा वर्ष 2005 से वह 12 तुगलक लेन में रहते आए हैं। वर्ष 2004 में कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन यू.पी.ए. बहुमत प्राप्त कर केन्द्र में सत्तारूढ़ हुआ था। उस वक्त गांधी परिवार के सदस्यों को स्पेशल प्रोटक्शन ग्रुप (एस.पी.जी.) की सुरक्षा मिली हुई थी और सुरक्षा के मद्देनज़र राहुल को एक बंगला दिया गया था। बंगला प्रियंका को भी दिया गया था, हालांकि वह सांसद नहीं थीं, किन्तु उन्हें एस.पी.जी. की सुरक्षा प्राप्त थी।

काफी समय निकलने के बाद नरेन्द्र मोदी ने निर्णय लिया कि गांधी परिवार के सदस्यों को एस.पी.जी. सुरक्षा की जरुरत नहीं है और स्पेशल प्रोटैक्शन ग्रुप का पूरा अमला सिर्फ एक आदमी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा करता है। यकीनन, 10 जनपथ लुटियन्स देहली की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ में से एक है। राजीव गांधी जब

- जैसा कि विदित ही है, उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए 22 अप्रेल तक का समय दिया गया है।
- राहुल गांधी 2005 से इसी 12, तुगलक रोड, बंगले में रह रहे थे।

वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव हार गए थे, जब वह 7 रेसकोर्स रोड आवास छोड़कर 10 जनपथ में आ गए थे। राजीव गांधी इससे पहले 1 अकबर रोड आवास से 7 रेसकोर्स रोड आए थे, 1 अकबर रोड आवास इन्दिरा गाँधी का था, जहाँ राजीव अपनी पत्नी सोनिया और दोनों बच्चों राहुल व प्रियंका के साथ रहा करते थे।

रेस कोर्स रोड स्थित 5,7,9 नम्बर के आवासों को आपस में मिलाकर प्रधानमंत्री आवास एवं दफ्तर में तब्दील कर दिया, जबकि राहुल गांधी डिस्क्वालिफाई होने से पूर्व ही सूरत के सैशन कोर्ट में एक अपील दायर कर चुके थे। राहुल गांधी को बतौर डिस्क्वालिफाईड सांसद, अपना आधिकारिक आवास खाली करने के लिए एक माह का समय भी दिया गया। अब 12 तुगलक लेन का सामान शिफ्ट करने के साथ ही यहाँ स्थित राहुल के दफ्तरों को भी शिफ्ट किया जाएगा। राहुल यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिला करते थे और वह कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणो को लेकर भी ऐसा किया गया। सूरत की एक जिला अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद मोदी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार ऐसा बरसों से कर रहे थे

आंतरिक सूत्र कहते हैं कि पिछले 18 वर्षो में यहाँ राहुल का काफी सामान जमा हो गया था और यह सब अब 10 जनपथ शिफ्ट किया जा रहा है। उम्मीद है कि राहुल भी वहाँ कुछ समय के लिए रहने चले जाएंगे। राहल गांधी ने यह बार-बार कहा है कि उनका खुद का कोई घर नहीं है, इसलिए देशभर के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें अपना घर ऑफर कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर भारत को मिला पहला एम्स

गुवाहाटी, 14 अप्रैल (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी स्थित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया। सूत्रों के अनुसार 1,123 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अस्पताल से न केवल असम के लोगों बल्कि क्षेत्र के अन्य राज्यों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है।

भाजपा ने ''डी.एम.के. फाइल्स'' जारी की

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। डी.एम.के. (द्रमुक) नेताओं द्वारा चुनाव के नामांकन में दायर हलफनामों में की गई सम्पत्ति की घोषणा से तथ्यों को निकाल कर भाजपा तमिलनाडु में यह जताने का प्रयास कर रही है कि समूची सत्तारुढ़ पार्टी और इसके वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। इसके लिए भाजपा ने बॉलीवुड हिंदी फिल्म ''कश्मीर फाइल्स'' की तर्ज पर ''डी.एम.के. फाइल्स'' जारी की है। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ''डी.एम.के. फाइल्स'' में भाजपा ने द्रमुक के वरिष्ठ नेताओं की चुनाव घोषणा पत्र में बताई गई सम्पत्ति के आधार पर उनके भ्रष्टाचार के कारनामों की जानकारी दी है। भाजपा का कहना है कि, द्रमुक नेताओं के पास 1.34 लाख करोड़ रू. की सम्पत्ति है।

कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है कर्नाटक में

भाजपा की, नये चेहरों को टिकट देने की गुजरात वाली रणनीति कामयाब होती नजर नहीं आ रही कर्नाटक में

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। कर्नाटक में अब चुनावी दांवपेच अपने अंतिम दौर में है। कहा जाए तो यहां जमीनी स्थिति और दिलचस्प घटनाक्रम निकट भविष्य के राजनीतिक प्रारूप का संकेत देते हैं क्योंकि निकट भविष्य में कुछ प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव।

जमीनी स्थिति को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा की डबल इंजन सरकार के राह आसान प्रतीत नहीं होती। हाल ही हुए अधिकांश चुनावी सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कांग्रेस आगे है और समान्य बहुमत की ओर बढ़ रही है, जबकि भाजपा उससे काफी पीछे दूसरे नम्बर पर है और जनता दल (सैक्यूलर) कांग्रेस के बजाए भाजपा के ही वोट काट रहा है।

इस स्थिति में, कर्नाटक में गुटबाजी से ग्रस्त भाजपा में क्या सरसराहट हो सकती है। यहां की भाजपा को एक ऐसी पार्टी माना जा सकता है जो पार्टियों के विलय और अधिग्रहण से बनी है क्योंकि इसके कुछ नेता या तो कांग्रेस से आए हैं अथवा जे.डी. (एस.) से। इसके अलावा टिकट ना दिए जाने के बाद कई नेताओं के इस्तीफों और एक मजबूत विद्रोही फैक्टर का उदय यह दर्शाता है कि बासवराज बोम्मई सरकार का चुनाव जीतकर पुनः सत्ता में आना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।

सी-वोटर व कई अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए कई स्वतंत्र सर्वेक्षण भी कांग्रेस के लिए थोड़ी बढ़त बताते हैं, लेकिन साउथ फर्स्ट नामक एक डिजिटल मीडिया संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वे में यह जोर देकर कहा गया है कि कर्नाटक एक खंडित जनादेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है क्योंकि तीनों ही प्रमुख प्रतिद्वंदी 224 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 113 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं।

यहाँ तक कि यह मीडिया संस्थान भी कांग्रेस को जादुई आंकड़े के निकट मानता है और भाजपा को सौ सीटों से कम के साथ दूसरे स्थान पर मानता है।

- गुजरात में जिन विधायकों के टिकट कटे थे, उन्होंने पार्टी का निर्णय बिना विरोध किये स्वीकार कर लिया था।
- पर, कर्नाटक में इस रणनीति के कारण बगावत जैसी स्थिति हो गयी है, जिस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है, भाजपा के लिये।

यदि भाजपा अपनी सरकार का गठन करना चाहेगी तो से जनता दल (एस.) के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। भाजपा को यह एहसास हो गया है कि उसकी स्थिति कठिन है क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है और पार्टी में गुटबाजी के साथ ही बोम्मई सरकार की छवि नकारात्मक है। भाजपा ने इस पहलू पर पाक पाने के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक में एक और वरिष्ठ भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। यदि कांग्रेस ने कल अपनी पार्टी के एक सीनियर नेता के वंशज को भाजपा के लिए खोया तो आज उसके खेमे में भाजपा का एक सीनियर नेता आ गया। भाजपा में टिकट दिए जाने से इंकार मिलने के बाद से लक्ष्मण सवाडी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावड़ी का टिकट कट गया है और टिकट कटते ही वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने सावड़ी को उनकी सीट अठानी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है।

'मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत घृणा नहीं है'

कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने ''द वायर'' के पत्रकार करण थापर को दिये गये एक इन्टरव्यू में मोदी पर ही फोकस रखा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के दो केन्द्र शासित प्रदेशों का रूप लेने से पहले, उसके अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल ''इल इन्फॉर्म्ड'' (गलत जानकारी युक्त) एवं ''इग्नोरैट'' (अज्ञानी) है, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचार से कोई परेशानी भी नहीं है।

''द वायर'' को दिये एक विस्फोटक इन्टरव्यू, जो मोदी सरकार को परेशान एवं लज्जित तथा विक्षुब्ध कर सकता है, में मलिक ने कहा, ''मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है।''

प्रतिष्ठित एवं जाने-माने पत्रकार करण थापर के साथ हुई बातचीत, जो वर्तमान राजनीति के कई आयामों को बड़ी साफगोई के साथ उजागर करती है, में मलिक ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में या तो ''गलत जानकारी'' है या फिर ''कोई जानकारी नहीं है'' ज्ञातव्य है कि सत्यपाल मलिक उस दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, जब फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था तथा उसी साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाया गया था।

इस बहुत विस्तृत इन्टरव्यू में, मलिक ने कहा कि पुलवामा में सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सी.आर.पी.एफ. की टुकड़ी पर हुआ हमला भारतीय व्यवस्था तथा गृह मंत्रालय की ''अक्षमता'' तथा ''लापरवाही'' का परिणाम था। उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। मलिक ने इस बात का विस्तृत विवरण दिया कि सी.आर.पी.एफ. ने किस तरह से अपने जवानों को ले जाने के लिये एयरक्राफ्ट की मांग की थी लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराने के लिये मना कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से उस मार्ग का ''सेनिटाइज़ेशन'' प्रभावी तरीके से नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने इन खामियों की जानकारी उस समय सीधे मोदी को दे दी थी, जब उन्होंने पुलवामा हमले के शीघ्र बाद ही, उन्हें (मलिक) को कॉरबैट पार्क के बाहर बुलाया था। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध लें तथा ये बातें किसी को नहीं बतायें। मलिक ने कहा कि एन.एस.ए. अजित डोवल ने भी उनसे कहा कि वे इस मामले में खामोश रहें तथा इस बारे में किसी से बात नहीं करें। मलिक ने कहा कि उन्हें तुरंत महसूस हो गया कि उनका इरादा पाकिस्तान पर दोषारोपण करना तथा सरकार एंव भाजपा को चुनावी लाभ प्राप्त करना था।

हिन्दी और अंग्रेजी-दोनों भाषाओं में बोलते हुये, मलिक ने यह भी कहा कि पुलवामा की घटना में गुप्तचर विभाग की गंभीर असफलता थी क्योंकि 300 किलोग्राम आर.डी.एक्स विस्फोटक से भरी कार पाकिस्तान से आई थी लेकिन 10-15 दिन से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर एवं गांवों में घूम रही थी तथा इसका पता किसी को नहीं चला तथा किसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मलिक ने विस्तार सहित बताया कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मलिक ने कहा, पुलवामा आंतकवादी हमला, सी.आर.पी.एफ. व गृह मंत्रालय की ''लापरवाही'' से हुआ था।
- सी.आर.पी.एफ. ने अपने जवानों को ''ट्रांसपोर्ट'' करने के लिये हवाई जहाज मांगा था, पर गृह मंत्रालय ने उनकी मांग ठुकरा दी थी तथा जिस सड़क से सी.आर.पी.एफ. के जवान जा रहे थे, उसको सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से ''सैनेटाइज़'' नहीं किया गया था।
- मलिक के अनुसार, जब यह तथ्य प्र.मंत्री के समक्ष उजागर किया, तो उन्हें कहा गया कि, वे चुप रहें। यह ही जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी उन्हें दिया था। मतलब साफ था, मोदी इस पुलवामा त्रासदी का राजनीतिक उपयोग करना चाहते थे, हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तान पर थोप कर।
- उन्होंने पुलवामा प्रकरण के बारे में यह भी कहा कि, यह सच है कि, 300 किलो आर.डी.एक्स पाकिस्तान से आया था, पर आर.डी.एक्स से लदी कार पन्द्रह दिन तक जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर घूमती रही, और किसी को जानकारी नहीं लगी।

क्या केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे?

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आप नेताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए और आज ही खुद उन्हें सी.बी.आई. ने आबकारी नीति मामले में 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का सम्मन भेज दिया है। केजरीवाल को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सी.बी.आई. ने दिल्ली आबकारी नीति में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सम्मन भेजा है। आप सांसद संजय सिंह ने इसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश करार दिया।